इकाई 16 औद्योगिकीकरण: अवधारणा एवं समस्याएँ

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 औद्योगिकीकरण की अवधारणा
16.3 भारत में औद्योगिक क्षेत्र के घटक
16.3.1 विभिन्न औद्योगिक गतिविधियाँ
16.3.2 उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण
16.4 उद्योगों का क्षेत्रीय केन्द्रीकरण
16.5 औद्योगिक रुग्णता
16.5.1 रुग्णता की परिभाषा
16.5.2 भारत में औद्योगिक रुग्णता के प्रभाव
16.5.3 बड़े उद्योगों की रुग्णता के लिए उत्तरदायी कारक
16.5.4 लघु उद्योगों में रुग्णता के लिए उत्तरदायी कारक
16.6 सारांश
16.7 शब्दावली
16.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
16.9 बोध प्रश्नों के उत्तर व दिशा-संकेत

16.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप जानेंगे :

- औद्योगिकीकरण की अवधारणा की व्याख्या;
- उद्योगों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आंकलन;
- औद्योगिकीकरण की भारी उद्योग कार्यनीति से उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण;
- औद्योगिक रुग्णता की परिभाषा; और
- औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी तत्त्व की व्याख्या।

16.1 प्रस्तावना

15 अगस्त 1947 के पश्चात् भारत के औद्योगिक पटल में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। देशी उद्यम अब विदेशी हितों की पूर्ति का साधन मात्र नहीं था। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में औद्योगिक उत्पादन कम था और जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही थी। अतः स्वतंत्रता के पश्चात्, जो कार्यनीति अपनायी गयी वह थी विशाल, आधारभूत और यंत्र निर्माण करने वाले उद्योगों में निवेश के माध्यम से द्रुतगामी औद्योगिकीकरण। भारी उद्योगों में निवेश बृहतर पूँजी भंडार के निर्माण में सहायक होता है। इससे एक स्वावलंबी और मज़बूत अर्थव्यवस्था की नींव पड़ती है क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का द्रुतगति से विस्तार होता है और उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी और कलपुर्जों के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता ।

प्रारम्भ में चूँकि उद्योगों में निवेश की मात्रा अधिक होने के कारण पक्वन अवधि (Gestation

Period) बहुत अधिक थी और लाभ देयता कम, इसलिए सरकार ने भारी उद्योगों को सार्वजनिक उद्यम के अन्तर्गत रखा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से भी आर्थिक योजनाओं से संबंधित नीतियों और विभिन्न लक्ष्य के साथ तालमेल रखते हुए कार्य करने की अपेक्षा रखी गयी। औद्योगिक विकास की इस कार्यनीति के फलस्वरूप ही भारत विश्व का दसवाँ औद्योगिक देश बन सका। भारत की औद्योगिक नीति की विवेचना अगली इकाई में विस्तार से होगी । यहाँ हम औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न वर्गों तथा औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य समस्याओं तक सीमित रहेंगे।

16.2 औद्योगिकीकरण की अवधारणा

संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद् (यूनेस्को) ने 1965 में औद्योगिकीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी :

"औद्योगिकीकरण आर्थिक विकास की वह प्रणाली है जिसमें राष्ट्रीय संसाधनों का मुख्य भाग तकनीकी रूप से अद्यतन एवं बहुशाखी ऐसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में प्रयोग हो जो सम्पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि-दर और सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन पर नियत्रंण रखने में सक्षम हो।" इस परिभाषा में निम्नलिखित कारकों पर जोर दिया गया है :

1) औद्योगिकीकरण के अंतर्गत उत्पादन की पुरानी तकनीकों को नई तकनीकों में परिवर्तन की प्रकिया सम्मिलित है।

2) औद्योगिकीकरण आर्थिक विकास की गति को तीव्र करता है जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो।

3) आधुनिकीकरण के द्वारा औद्योगिकीकरण बहु-क्षेत्रक आधार तैयार करके बहुशाखी राष्ट्रीय उद्योग को विकसित कर सकता है। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि भारी एवं पूँजीगत पदार्थ क्षेत्रक का विकास करना औद्योगिकीकरण की पूर्व शर्त हैं। किसी अर्थव्यवस्था का औद्योगिकीकरण अन्य नई क्षेत्रकों में किया जा सकता है और इससे उत्पादित अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात करके पूँजीगत पदार्थों का आयात किया जा सकता है।

संक्षेप में, यह परिभाषा अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण के लिए किसी संकीर्ण या स्थिर क्रम की अनुगमन के निर्देश नहीं देती।

इस विचारधारा के विपरीत मार्क्सवादी अर्थशास्त्र में 'औद्योगिकीकरण' दो भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। संकीर्ण रूप में यह भारी और आधारभूत उद्योगों के विकास और स्थापना या उत्पादन के साधनों के उत्पादन के लिए प्रयोग होता है। किन्तु उदारवादी रूप में यह उस औद्योगिक क्रांति की ओर संकेत करता है जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों के लिए उत्पादन की औद्योगिक (तकनीकी) विधियों को अपनाया जाता है।

प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में भारी उद्योगों की स्थापना की जाती है। फिर जैसे-जैसे यह प्रक्रिया जोर पकड़ती है और अर्थव्यवस्था का औद्योगिक आधार बनता जाता है वैसे-वैसे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली में रूपान्तरित होने लगती है। इस प्रकार औद्योगिकीकरण की मार्क्सवादी परिभाषा औद्योगिकीकरण के विभिन्न क्रमों की व्याख्या करती है। जिसमें पहले भारी उद्योगों अथवा उत्पादन के साधनों का उत्पादन करके एक औद्योगिक आधार बनाया जाता है। तत्पश्चात् दूसरे चरण में सम्पूर्ण

अर्थव्यवस्था उत्पादन की औद्योगिक विधियों में परिवर्तित हो जाती है। औद्योगिकीकरण के मार्क्सवादी स्वरूप के मूल में सोवियत संघ का विकास निहित है। प्रारम्भिक चरण में सोवयित संघ ने भारी उद्योगों का विकास किया। सोवियत संघ के पास लघु उद्योगों और भारी उद्योगों को विकसित करने की क्षमता थी क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी थी और भूमि, खाद्यान्न, परिवहन और संचार साधन आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। साथ ही उत्पादन की खपत के लिए बहुत बड़ा घरेलू बाजार भी सोवियत संघ के पास था। फिर सोवियत संघ ने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित करने का निर्णय तत्काल न लेकर आगे चल कर लिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में परिस्थितियाँ भी सोवियत संघ जैसे ही थी। भारत में लघु और भारी दोनों प्रकार के उद्योग विकसित हो सकते थे किन्तु भारतीय योजनाकारों ने पहली अवस्था में भारी उद्योगों को विकसित करने का निर्णय लिया। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारी उद्योगों में वे सब उद्योग सम्मिलित हैं जिनमें उन पूँजीगत पदार्थों का उत्पादन होता है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत रेलवे और आधारिक संरचना (Infrastructure) जिसमें जल विद्युत तथा थर्मल विद्युतशक्ति आदि परियोजनाएँ भी सम्मिलित हैं। भारी उद्योगों के विकास को औद्योगिक नीति 1956 में शामिल किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुविद प्रो. महलनोबिस (Mahalanobis) भारतीय आर्थिक विकास की आधार भूत कार्यनीतिक रूप में भारी उद्योगों के विकास के पक्षधर थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनके विचारों के समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू भारी उद्योगों के विकास को औद्योगिकीकरण का समानार्थी मानते थे। नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था :

"यदि हमें औद्योगिकीकरण करना है तो प्रमुख आवश्यकता है कि हम उन भारी उद्योगों में निवेश करें जो मशीनें बनाती हैं। एक अन्य संदर्भ में उन्होंने कहा था कि कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि हम भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों का विकास करे। निसंदेह देश में लघु उद्योग होने चाहिए किन्तु जब तक हम अपना ध्यान औद्योगिक विकास के उपयोग में आने वाली मशीनों का उत्पादन करने वाले मूल उद्योगों पर केन्द्रित नहीं करते तब तक राष्ट्र का तीव्र गति से औद्योगिकरण सम्भव नहीं है।"

दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू के औद्योगिकीकरण सम्बंधी दर्शन को सम्मिलित किया गया। जिसमें स्पष्ट कहा गया है "दीर्घकाल में औद्योगिकीकरण की दर तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि कोयला, बिजली, लोहा और इस्पात, भारी मशीनरी, रसायन और भारी उद्योगों के बढ़ते उत्पादन पर निर्भर करेगी जो पूँजी निर्माण की क्षमता को बढ़ाते हैं। भारत को यथा सम्भव उत्पादक वस्तुओं के आयात से जल्द मुक्त कराना एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। ताकि दूसरे देशों से आवश्यक उत्पादक वस्तुओं की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों के कारण पूँजी संचय में बाधा न आए। अतः भारी उद्योगों का यथासम्भव तीव्र गति से विस्तार करना आवश्यक है।"

भारी उद्योगों में पक्वन अवधि (Gestation Period) बहुत लम्बी होती है और लाभ की दर अपेक्षाकृत कम जिस कारण निजी क्षेत्रक भारी उद्योगों में निवेश करने का इच्छुक नहीं होता। अतः भारी उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को दिया गया है। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रक संवृद्धि का इंजन होगा तथापि निजी क्षेत्रक से भी यह अपेक्षा रखी गयी कि वह सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रयासों में सहायक होगा।

बोध प्रश्न 1

1) औद्योगिकीकरण के अर्थ की विवेचना करें। क्या औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर विकास के लिए उद्योगों के स्थिर क्रम की अनुगमन की आवश्यकता होती है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

16.3 भारत में औद्योगिक क्षेत्र के घटक

खंड एक में हमने जाना कि आर्थिक गतिविधियाँ मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बंटी होती हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्रकों के रूप में भी जाना जाता है यथा प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक । इस विभाजन के अनुसार औद्योगिक गतिविधियाँ माध्यमिक क्षेत्र में आती है। आपने खंड एक में गौर किया होगा कि माध्यमिक क्षेत्रक के अन्तर्गत दो मुख्य वर्ग आते हैं : उद्योग और निर्माण। निर्माण की गतिविधियाँ माध्यमिक क्षेत्र का भाग होते हुए भी औद्योगिक क्षेत्र का अंश नहीं है। 1999-2000 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 27 प्रतिशत माध्यमिक क्षेत्र से आया।

16.3.1 विभिन्न औद्योगिक गतिविधियाँ

औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य तीन गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :

i) विनिर्माण (Manufacturing)

ii) विद्युत, गैस और जल प्रदाय (Electricity, Gas and Water Supply)

iii) खनन और खादान (Mining and Quarrying)

विनिर्माण की गतिविधि के भी दो मुख्य उपविभाग हैं :

i) कारखाना क्षेत्रक (Factory Sector)

ii) गैर कारखाना क्षेत्रक (Non-Factory Sector)

कारखाना क्षेत्रक को संगठित क्षेत्र या पंजीकृत क्षेत्र भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि वह सभी औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें दस या अधिक श्रमिक शक्ति (Power) की मदद से कार्य करते हैं उनको भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत करना आवश्यक है। इस प्रकार की यह औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत क्षेत्रक कहलाती हैं। शेष औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें दस से कम श्रमिक शक्ति (Power) की मदद से कार्य करती हैं वह गैर कारखाना क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। यह उप क्षेत्रक अपंजीकृत या असंगठित क्षेत्रक भी कहलाता है। सामान्यतः इसमें घरेलू उद्योग और गैर घरेलू लघु उद्योग आते हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रक की विभिन्न इकाइयों के हिस्सा तालिका 16.1 में दिए गए हैं।

तालिका 16.1 : औद्योगिक गतिविधियों का प्रतिशत वितरण

(1993-94 के मूल्य दर, 1999-2000 के लिये)

क्रमांक	उपक्षेत्रक	भागेदारी प्रतिशत
1.	विनिर्माण (क+ख)	63.57
	क) पंजीकृत	42.01
	ख) गैर पंजीकृत	21.56
2.	विद्युत	9.29
3.	खनन	8.55
4.	निर्माण	18.96
5.	औद्योगिक क्षेत्रक (1+2+3)	81.04
6.	माध्यमिक क्षेत्रक (1+2+34)	100.00

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) निरन्तर सभी औद्योगिक इकाइयों से संबंधित आँकड़े एकत्र करता है। प्रत्येक वर्ष कारखाना क्षेत्रक के विभिन्न उत्पादन पक्षों में जानकारी वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के रूप में एकत्रित की जाती है। दूसरी ओर गैर कारखाना क्षेत्रक के आँकड़े हर पाँच वर्ष के अंतराल में एकत्र किए जाते हैं। केन्द्रीय सांख्यकीय के संगठन (CSO) ने औद्योगिक क्षेत्रक को 20 औद्योगिक समूहों में विभाजित किया है। यह वर्गीकरण द्विअंकीय वर्गीकरण है। प्रत्येक समूह आगे चलकर त्रिअंकीय (3 digit level) स्तर पर वर्गीकृत होता है। उदाहरण के लिए कागज़ उत्पादन द्विअंकीय समूह में आता है। इसके अंतर्गत त्रिअंकीय स्तर में समाचार मुद्रण, मुद्रण और विभिन्न कागज उत्पादन के समूह आते हैं। तालिका 16.2 में ये औद्योगिक समूह (2 digit level) अपनी पंजीकृत विनिर्माण में भागेदारी के साथ प्रस्तुत है ।

तालिका 16.2 : पंजीकृत विनिर्माण निर्गत में औद्योगिक समूहों की भागेदारी

उद्योग का कोड	उद्योग का नाम	प्रतिशत भागेदारी (1997-98)
20-21	खाद्य उत्पाद	9.32
22	पेय पदार्थ और तंबाकू	3.09
23	सूती वस्त्र उद्योग	4.27
24	ऊनी, सिल्क और तंतु वस्त्र	3.79
25	जूट और अन्य वनस्पति तंतु वस्त्र	0.95
26	वस्त्र उत्पाद	2.52
27	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	0.29
28	कागज और कागज उत्पाद	2.82
29	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	0.91
30	रसायन और रासायनिक उत्पाद	18.57
31	रबड़ और रबड़ उत्पाद	6.19
32	गैर धातु मिनरल उत्पाद	4.47
33	आधारभूत धातु और एलॉय	15.95
34	धातु उत्पाद (मशीनरी और यंत्रों के अतिरिक्त)	2.49
35-36	परिवहन यंत्रों के अतिरिक्त मशीनरी और यंत्र	14.52
37	परिवहन यंत्र और पुर्जे	7.98
38	अन्य विनिर्माण उद्योग	1.88
	कुल	**100.00**

16.3.2 उपयोग पर आधारित वर्गीकरण

इससे पहले अनुभाग में वर्णित औद्योगिक गतिविधियों का समान रूप से आर्थिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए अन्य उत्पादों के विनिर्माण में लोहा और इस्पात आधारभूत मध्यस्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं जबकि रोटी एक उपभोग के लिए उपयोग में आने वाला भोज्य पदार्थ है। लोहा व इस्पात और भोज्य पदार्थ के उत्पादन में असंगति (Variation) अर्थव्यवस्था के लिए एकदम भिन्न संवृद्धि मार्ग निर्धारित करता है। अतः औद्योगिक गतिविधियों को उनके उत्पादों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करना आवश्यक है।

विनिर्माण गतिविधियाँ उपयोग के आधार पर चार मुख्य समूहों में विभाजित है। इस प्रकार का उपयोगाधारित वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को पहचानने में सहायक होता है। ये चार उपयोगाधारित वर्ग हैं :

1) आधारभूत वस्तुएँ (Basic Goods)

2) मध्यस्थ वस्तुएँ (Intermediate Goods)

3) पूँजीगत वस्तुएँ (Capital Goods)

4) उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer Goods)

उपभोक्ता वस्तुएँ दो अनुवर्गो में बँटी हैं :

1) स्थायी उपभोक्ता वस्तुएँ

2) अस्थायी उपभोक्ता वस्तुएँ

आधारभूत वस्तुओं में नमक, खाद, भारी रसायन, सीमेंट, आधारभूत धातु, विद्युत और खनन आते हैं। वस्त्र निर्माण, लकड़ी, समाचार मुद्रण, चमड़ा, रबड़ उत्पाद, अधातु खनिज उत्पाद और रसायन के कुछ वर्ग मध्यस्थ वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर पूँजीगत वस्तुओं में सभी प्रकार की मशीनरी, मशीनी यंत्र और परिवहन यंत्र आते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में फर्नीचर और स्थिर वस्तुएँ, दफ्तरी और घरेलू समान, विद्युत और दूरसंचार के साधन, वाहन आदि सम्मिलित हैं जबकि अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं में खाद्य उत्पाद, वस्त्र, फुटवेयर, कागज उत्पाद, मैषज पदार्थ (Drugs) व दवाईयाँ आदि शामिल हैं।

बोध प्रश्न 2

1) निम्नलिखित में भेद बताएँ :

i) माध्यमिक क्षेत्रक और औद्योगिक क्षेत्रक

.....

.....

.....

ii) विनिर्माण क्षेत्रक और औद्योगिक क्षेत्रक

.....

.....

.....

iii) स्थायी उपभोक्ता वस्तुएँ और अस्थायी उपभोक्ता वस्तुएँ।

.....

.....

.....

16.4 उद्योगों का क्षेत्रीय केन्द्रीकरण

भारत में उद्योग संबंधित विचार वस्तु में एक विषय क्षेत्रीय असंतुलन है जिस पर हमने खंड एक में विचार किया । हमने जाना कि कुछ राज्य आर्थिक चरों (Variables) में पिछड़े हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों की स्थिति बेहतर है। यह असमानता समय के साथ-साथ बढ़ती गई जिसके परिणामस्वरूप निर्धन राज्य अधिक निर्धन और सम्पन्न राज्य और अधिक सम्पन्न

होते गए। यह तथ्य औद्योगिक विकास में भी देखा गया ।

जैसे-जैसे देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में प्रगति हुई क्षेत्रीय संकेन्द्रण की प्रवृत्ति औद्योगिकीकरण में आती गई। चार राज्य, जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात मुख्य हैं, को औद्योगिकीकरण का लाभ मिला। तालिका 16.3 से ज्ञात होता है कि 1997-98 में इन चार राज्यों में कुल कारखानों का 53 प्रतिशत रहा और कुल कारखाना रोजगार का 48.5 प्रतिशत। औद्योगिक वर्धित मूल्य (Value Added) में इन राज्यों की भागीदारी क्रमशः 51 प्रतिशत और 47 प्रतिशत थी। जबकि इन चार राज्यों में देश की कुल जनसंख्या का केवल 28.7 प्रतिशत रहता है। इसी से राज्यों में औद्योगिक असमानता का पता चलता है।

तालिका 16.3 : उद्योग की क्षेत्रीय स्थिति 1997-98

प्रतिशत

राज्य	कारखानों की संख्या	स्थिर पूँजी में लोग	रोजगार + मूल्य	बर्हिगमन	वर्धित मूल्य	जनसंख्या
महाराष्ट्र	15.15	18.1	14.76	21	21.67	9.33
तमिलनाडू	14.57	8.26	12.85	10.01	8.66	6.60
गुजरात	9.88	15.24	8.80	12.87	9.23	4.88
आंध्र प्रदेश	13.84	7.52	12.09	6.99	7.43	7.86
कुल (चार राज्यों)	53.44	49.11	48.5	50.75	46.98	28.67
शेष राज्यों	46.56	50.89	51.5	49.25	53.02	71.33
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

महाराष्ट्र को अधिकतम लाभ पहुँचा है। क्योंकि कुल कारखाना उत्पाद में इस राज्य की भागीदारी 21 प्रतिशत थी जो मूल्य जोड़ने पर 22 प्रतिशत होती है। जबकि इस राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 9 प्रतिशत है। दूसरी ओर बिहार है जिसकी जनसंख्या तो बहुत बड़ी है किन्तु उसके अनुपात में कारखानों की श्रेणी में यह राज्य बहुत नीचे है। कारखानों की संख्या, औद्योगिक निर्गत और उत्पादन की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत ऊँचा है हालाँकि इस राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत भी बहुत अधिक है। इसी कारण इसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता।

कारखानों की वृद्धि, औद्योगिक निर्गत और मूल्य में क्षेत्रीय असन्तुलन यह संकेत करता है कि देश एक सन्तुलित क्षेत्रीय औद्योगिक प्रणाली विकसित करने में असफल रहा है।

16.5 औद्योगिक रुग्णता

भारत के बड़े, मध्यम और लघु उद्योग औद्योगिक रुग्णता से ग्रस्त हैं। अतः इस समस्या का अध्ययन करना उपयुक्त होगा।

16.5.1 रुग्णता की परिभाषा

जब एक औद्योगिक इकाई वर्षों तक घाटे में रहती है और इस प्रक्रिया में संचित घाटे से उस इकाई की निवल सम्पत्ति (Net Worth) का ह्रास होता है तो उस स्थिति को औद्योगिक

रुग्णता कहते है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अनुसार एक रुग्ण कम्पनी से तात्पर्य ऐसी मध्यम या बड़ी औद्योगिक कम्पनी (लघु उद्योग नहीं) से है जिसकी वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि उसकी सम्पूर्ण निवल सम्पत्ति के बराबर या उससे अधिक हो तथा उस वित्तीय वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष में भी उसे नकद घाटा हुआ हो। इस परिभाषा के अंतर्गत सरकारी कम्पनियाँ, शीपिंग कम्पनियाँ और छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ/आनुवांशिक इकाइयाँ नहीं आती है।

रुग्ण कंपनी घोषित होने से पहले इकाई कमजोर हो जाती है। जब कोई इकाई दुर्बल होने लगे उस अवस्था में कार्यवाही करना आवश्यक है ताकि वह रुग्ण इकाई के श्रेणी में न जा सके। यदि वर्तमान लेखा वर्ष से पूर्व के पाँच लेखा वर्षों में उस इकाई का संचित घाटा सर्वाधिक निवल मूल्य के बराबर या 50 प्रतिशत से अधिक है वह कमज़ोर इकाई कहलाती है।

'निवल मूल्य' से तात्पर्य मुक्त आरक्षिति (Free Reserves) और युक्त पूँजी (Paid-up capital) के योग से है। मुक्त आरक्षिति का अर्थ है : लाभ और भागेदारी बढ़ौती खाता (Share Premimum) से बचाए गए सभी आरक्षिति।

लघु उद्योगों में औद्योगिक रुग्णता बड़े पैमाने पर व्याप्त है। 1989 की रुग्ण लघु उद्योग इकाई की परिभाषा में कहा गया है कि यदि किसी लघु उद्योग इकाई की संचित हानि एक लेखावर्ष के अंत में पिछले पाँच वर्षों के उस इकाई के निवल मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हो तो वह लघु उद्योग इकाई रुग्ण मानी जाएगी।

16.5.2 भारत में औद्योगिक रुग्णता का प्रभाव

पिछले दशक के दौरान भारत में औद्योगिक रुग्णता बढ़ रही है। इसने न केवल कुछ परम्परागत उद्योगों जैसे— सूती वस्त्र, जूट, चीनी और कागज उत्पादन में प्रवेश किया है बल्कि उन महत्वपूर्ण उद्योगों को भी प्रभावित किया है जो विशेषतः स्वतंत्रता के बाद स्थापित किए गए जैसे प्रोद्योगिकी, रसायन, लोहा और इस्पात तथा सीमेंट आदि।

औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती रुग्णता के कारण उद्योगों को दिए गए ऋण की एक बहुत बड़ी रकम निधि रुद्ध (Locked up) है जो संसाधनों की बरबादी की द्योतक है।

तालिका 16.4 : मार्च 1994 के अंत में भारत में औद्योगिक बीमारी

	बीमार इकाइयों की संख्या	कुल बैंक ऋण का निधि-रोध (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
1. गैर SSI बीमार इकाइयाँ	1909	8151	59.5
2. SSI कमज़ोर इकाइयाँ	591	1864	13.6
3. SSI बीमार इकाइयाँ	2,56,452	3680	26.9
कुल	**2,58,952**	**13,695**	**100.0**

31 मार्च 1994 तक बड़ी और मध्यम उद्योग क्षेत्रक में (गैर लघु उद्योग क्षेत्रक) 1,909 रुग्ण इकाइयाँ थी। जिनमें कुल 8,151 करोड़ रुपये बैंक ऋण का निधिरोध थी। इनके साथ 591 अन्य गैर लघु उद्योग इकाई रुग्ण थी उनमें कुल 1,864 करोड़ रुपये बैंक ऋण का निधि रोध था। दोनों का योग करने पर बड़ी और मध्यम उद्योग क्षेत्रक में रुग्ण इकाइयों में कुल 10,015 करोड़ रुपये की निधिरोध था जो कुल बैंक ऋण का 73 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्रक में 2,56,452 बीमार इकाइयाँ थी जिनमें 3680 करोड़ रु.

निधिरोध था। इस प्रकार पता चलता है कि कुल बैंक ऋण का 27 प्रतिशत रुग्ण इकाइयों में अवरूद्ध था।

तालिका 16.5 : उद्योगों के अनुसार बड़े और मध्यम उद्योगों की रुग्ण इकाइयों का वर्गीकरण

उद्योग	रुग्ण एवं दुर्बल इकाइयाँ	कुल का प्रतिशत	बकाया बैंक ऋण	कुल का प्रतिशत
वस्त्र	466	18.7	2018	20.1
प्रौद्योगिकी	297	11.9	1303	13.0
रसायन	207	8.3	866	8.6
लोहा और इस्पात	142	5.7	749	7.5
विद्युत	87	3.5	768	7.7
कागज	134	5.4	405	4.0
सीमेंट	67	2.7	336	3.4
चीनी/शकर	32	1.3	100	1.0
जूट	44	1.8	187	1.9
रबड़	52	1.7	129	1.3
अन्य	975	39.0	3154	31.5
कुल	**2500**	**100.0**	**10,015**	**100.0**

तालिका 16.5 में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि वस्त्र, प्रौद्योगिकी, रसायन, लोहा और इस्पात तथा विद्युत ये पांच उद्योग में बड़े व मध्यम उद्योग की 1199 कमजोर और बीमार इकाइयाँ आती हैं और इनमें कुल 5704 करोड़ रु. की बैंक ऋण निधि रूद्ध है (कुल बैंक ऋण का 57 प्रतिशत)। यह द्योतक है कि इन उद्योगों में बीमारी की मात्रा बहुत अधिक थी। निसंदेह, कागज, सीमेंट, शकर, जूट, रबड़ आदि उद्योग में भी बीमार इकाइयाँ थी किन्तु इनमें बीमार इकाइयों की संख्या कम थी।

भारत में राज्य अनुसार औद्योगिक रुग्णता का विश्लेषण

विभिन्न राज्यों की रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों (SSI) और गैर लघु उद्योगों की बीमार व दुर्बल इकाइयों तथा उनमें बकाया बैंक ऋण से संबंधित आँकड़े तालिका 16.6 में दिए गए हैं। इकाइयों की संख्या भ्रमित करती है। क्योंकि संबद्ध इकाइयों का आकार भिन्न हो सकता है। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण संकेतक बकाया बैंक ऋण है। इसे आधार मानकर एकत्र किए आँकड़े बताते हैं कि औद्योगिक रूप से उन्नत सात राज्यों (महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल) की बीमार और कमजोर गैर लघु उद्योगों (Non SSI) इकाइयों में 7,376 करोड़ रुपये (कुल का 73.6 प्रतिशत) बकाया बैंक ऋण था। इन सात राज्यों में रुग्ण और कमजोर लघु उद्योग इकाइयों में बकाया बैंक ऋण 2593 करोड़ था (कुल का 70.5 प्रतिशत)। लघु और गैर लघु उद्योगों को मिलाकर इन राज्यों में कुल बकाया बैंक ऋण की राशि 9,969 करोड़ रुपये (72.7 प्रतिशत) थी। सबसे ऊपर महाराष्ट्र था जिसमें अवरुद्ध बैंक ऋण 2677 करोड़ रुपये (19.5 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल में 17.61 करोड़ रुपये (13 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश में 1256 करोड़ रुपये (9.2 प्रतिशत) बकाया बैंक ऋण था।

तालिका 16.6 : 31 मार्च 1994 को भारत में औद्योगिक बीमारी का राज्यों के अनुसार विश्लेषण

	इकाइयों की संख्या		बकाया बैंक ऋण (करोड़ रुपये)			कुल का
	Non-SSI	SSI	Non-SSI	SSI	Total	प्रतिशत
1. महाराष्ट्र	436	21,350	1909	768	2677	19.5
2. पश्चिम बंगाल	292	56,083	1401	360	1761	12.9
3. उत्तर प्रदेश	201	33,915	948	335	1275	9.3
4. आंध्र प्रदेश	263	13,915	993	263	1256	9.2
5. गुजरात	222	7,812	862	235	1097	8.1
6. तमिलनाडु	207	8,125	644	428	1070	7.8
7. कर्नाटक	151	15,145	627	204	831	6.1
उपयोग(1से 7 तक)	1772 (70.9)	156272 (60.9)	7376 (73.6)	2593 (70.5)	9969 (72.7)	72.7
8. केरल	85	10,272	519	169	688	5.0
9. हरियाणा	88	1,669	366	80	446	3.3
10. बिहार	71	17,063	322	114	436	3.2
11. मध्य प्रदेश	117	9,795	283	144	427	3.1
12. उड़ीसा	61	17,235	281	75	356	2.6
13. राजस्थान	82	14,665	225	75	300	2.2
14. पंजाब	51	2,434	122	65	187	1.4
15. असम	35	14,210	145	40	185	1.4
16. अन्य	138	12,317	376	325	701	5.1
कुल का योग (1 से 16 तक)	**2500 (100.0)**	**256452 (100.0)**	**10015 (100.0)**	**3680 (100.0)**	**13695 (100.0)**	**100.0**

तालिका 16.7 : भारत में औद्योगिक बीमारी में वृद्धि

	बकाया बैंक ऋण (करोड़ रुपये) दिसम्बर 1980	मार्च 1994	औसत वार्षिक संवृद्धि-दर
Non SSI इकाइयाँ (बड़ी और मध्यम)	1,520	10,015	15.6
SSI बीमार इकाइयाँ	306	3,680	24.9
कुल	**1,826**	**13,695**	**16.8**

औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि

तालिका 16.7 में 1981-94 तक उद्योगों में फैली रुग्णता की जानकारी दी गई है। यह आँकड़े बताते हैं कि बड़े और मध्यम इकाइयों में कुल बकाया बैंक ऋण दिसम्बर 1980 में 1520 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1994 में 10015 करोड़ रुपये हो गया। इसके विपरीत लघु उद्योग क्षेत्रक में बकाया बैंक ऋण दिसम्बर 1980 के 306 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1994 में 3680 करोड़ रुपये हो गया। इससे ज्ञात होता है कि औद्योगिक रुग्णता की घटना गैर लघु उद्योग इकाइयों की तुलना में लघु उद्योग इकाइयों में तीव्र गति से बढ़ी। दोनों

क्षेत्रकों का योग करने पर बकाया बैंक ऋण 1826 करोड़ से बढ़कर 13695 करोड़ रुपये तक पहुँचा जो 16.8 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि-दर की ओर संकेत करता है।

16.5.3 बड़ी इकाई में रुग्णता के लिए उत्तरदायी कारक

औद्योगिक बीमारी के लिए दो प्रकार के कारक उत्तरदायी हैं–

बाह्य और आंतरिक

बाह्य कारकों की सूची में सम्मिलित हैं :

1) उत्पादन वितरण और कीमत से संबंधित सरकारी नीतियाँ

2) योजनाओं में नई प्राथमिकताओं के फलस्वरूप निवेश के ढांचे में परिवर्तन

3) बिजली, परिवहन और कच्चे माल की कमी

4) खराब औद्योगिक संबंध

औद्योगिक रुग्णता में सरकारी नीति भी कई मायनों में जिम्मेदार रही है। उदाहरण के तौर पर नियंत्रित वस्त्र योजना से कपास की कीमत भी नहीं निकल पाती और यही कपड़ा उद्योग की रुग्णता का मुख्य कारण बना। इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयले के मूल्य पर कठोर नियंत्रण थोपे जाने के कारण कोयला उद्योग में बीमारी फेली। किन्तु राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद कोयले का मूल्य तीन साल की अवधि में ढाई गुना बढ़ा। ऐसी तर्कहीन नीतियाँ औद्योगिक रुग्णता का कारण बनी।

दूसरा कारक जो औद्योगिक बीमारी के लिए उत्तरदायी है वह है मजदूरी और आय के लिए एक स्पष्ट नीति का न होना। भारतीय रिर्जव बैंक, स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों, जीवन बीमा निगम और इसी प्रकार के अधिक लाभ कमाने वाले अन्य उद्योगों के कर्मचारियों को सरकार अधिक मजदूरी और सुविधायें देती रही है। इन उद्योगों की देखा-देखी अन्य उपक्रमों/उद्योगों में कार्यरत श्रमिक भी अधिक मजदूरी की मांग करते है। सरकार का नियम बनना चाहिए कि समान योग्यता वाले कर्मचारी की मजदूरी सभी उद्योगों में एक समान या लगभग एक समान हो। ऐसा न करने पर उद्योगों में हड़ताल की स्थिति आ जाती है।

आतंरिक कारकों में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण है :

1) मालिकों का कुप्रबंध

2) निधि पद्यांतरण (Diversion of Fund)

3) लाभांश से संबंधित गलत नीति

4) अत्यधिक उपरिव्यय

5) मशीनरी और अन्य उपकरणों के मूल्य ह्रास के प्रावधान का अभाव

6) मांग का अति अनुमान

16.5.4 लघु उद्योग इकाइयों में रुग्णता के लिए उत्तरदायी कारक

विभिन्न अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित कारक प्रकाश में आते हैं :

उद्योग प्रबन्धन के आधारभूत नियमों की अनदेखी : अनेक लघु उद्यमी थोड़े सी आरम्भिक पूँजी के साथ उद्योग प्रारम्भ करते हैं। तथा आगे आने वाले वर्षों में आन्तरिक वित्तीय शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। वे लघु काल के लिए कर्ज लेते हैं किन्तु मध्यम काल की परियोजनाओं में निवेश करते हैं जिससे संसाधन का संकट उत्पन्न होता है। इन लघु निवेश कर्ताओं के संकट का सामना करने की असमर्थता के कारण ऐसी इकाइयों में रुग्णता की स्थिति उत्पन्न होती है।

प्रबन्धन कुशलता की कमी : यह देखा गया है कि युवा उद्यमी रोमांचकारी विचारों के साथ उद्यम प्रारम्भ करते हैं। वे सुविधा सम्पन्न कार्यालय स्थापित करने के लिए उपरि व्यय बढ़ा लेते हैं। और ब्याज की ऊँची दरों पर उधार लेते हैं। यह उद्यमी लागत कम रखने की ओर विशेष ध्यान नहीं देते और विभिन्न ग्राहकों को उधार देते हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यतिक्रम अधिक होता है। अतः अनुभवी प्रबन्धन का अभाव और बाजार की अपर्याप्त जानकारी रुग्णता का कारण बन जाती है।

सामर्थ्य का न्यून उपयोग : कच्चे माल की अनुपलब्धता या मांग में कमी या कार्य पूँजी की कमी के कारण भी लघु उद्योगों में रुग्णता पैदा होती है।

मुख्य उद्योगों द्वारा भुगतान न होना : अनेक लघु उद्योग इकाई बड़े इकाइयों को सामान देती है। यह बड़े उद्योग लघु उद्यमियों को कई महीनों तक भुगतान नहीं करते जिसके फलस्वरूप छोटे उद्योगों के पूँजी प्रवाह में बाधा आती है और छोटे उद्यम रुग्ण हो जाते हैं।

सरकार ने विभिन्न स्तर पर रुग्णता को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। 1985 में रुग्ण औद्योगिक कम्पनी एक्ट पास किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण इकाइयों के निष्पादन को अनुवीक्षण (Monitor) करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया। सरकार ने एक निश्चित समय अवधि में मुख्य उद्योगों द्वारा लघु उद्योगों को भुगतान के लिए बाध्य करने वाला नियम भी पास किया जिसके पालन न करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा। सरकार के विविध उपायों के उपरान्त भी औद्योगिक रुग्णता को नियंत्रित करना संभव नहीं हो सका। अतः सरकार को अब तक के मापदण्डों का पुनरनिरिक्षण करना होगा।

बोध प्रश्न 3

1) रुग्ण उद्योग कम्पनी एक्ट (1985) के अनुसार रुग्ण और दुर्बल इकाई की परिभाषा क्या है ?

.....

.....

.....

.....

.....

2) बड़ी और मध्यम इकाइयों में औद्योगिक रुग्णता के पाँच मुख्य कारण बताएं।

.....

.....

.....

.....

.....

3) लघु उद्योगों में औद्योगिक रुग्णता के तीन प्रमुख कारणों की सूची बनाएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

16.6 सारांश

औद्योगिकीकरण के अंतर्गत उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन की प्रक्रिया आती है जो पुरानी से नयी तकनीक के रूप में होती है। मार्क्सवादी अर्थशास्त्र की पुस्तकों में औद्योगिकीकरण के दो चरण दिए गए है। प्रथम चरण में भारी और मूल उद्योगों की स्थापना आती है। दूसरे चरण में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को औद्योगिक उत्पादन प्रणालियों में रूपान्तरित करना आता है। मार्क्सवाद के अनुसार विकासोन्मुख गैर औद्योगिक देशों में औद्योगिकीकरण का सोवियत मॉडल ही एकमात्र सही प्रणाली है। गैर मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीयों ने कोई क्रम निर्धारित नहीं किया।

भारत में औद्योगिकीकरण के मार्ग में दो कठिनाईयाँ हैं : औद्योगिक इकाइयों का क्षेत्रीय केन्द्रीकरण और इकाइयों की रुग्णता।

भारत में कुछ राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा औद्योगिक रूप से अधिक विकसित है ये राज्य हैं : महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।

औद्योगिक रुग्णता उस स्थिति को कहते हैं जब किसी इकाई को वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में हानि होती है और इस प्रक्रिया में होने वाले घाटे के कारण उसका निवल मूल्य ह्रास होता है। यदि निवल मूल्य ह्रास 50 प्रतिशत तक हो तो वह इकाई कमजोर मानी जाती है। निवल मूल्य ह्रास 100 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर इकाई को बीमार माना जाता है।

बड़े और मध्यम उद्योगों के साथ-साथ लघु उद्योगों में भी औद्योगिक बिमारी व्याप्त है। औद्योगिक रुग्णता मुख्यतः पांच उद्योगों में केन्द्रित है अर्थात वस्त्र, इंजीनियरीं, रसायन, लोहा इस्पात और विद्युत उद्योग। दूसरी ओर सात राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल में औद्योगिक बिमारी का केन्द्रीकरण दर्शित होता है।

1981-94 की अवधि में भारत में बकाया बैंक ऋण के आधार पर मापी गई औद्योगिक रुग्णता के प्रतिवर्ष 16.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। गैर लघु उद्योगों की इकाइयों में यह वृद्धि-दर 15.6 प्रतिशत थी जबकि लघु उद्योगों की इकाइयों में औद्योगिक रुग्णता की वृद्धि-दर 24.9 प्रतिशत थी। सरकार ने औद्योगिक रुग्णता की समस्या दूर करने के लिए अनेक उपाय किए किन्तु ये उपाय सभी उद्योगों में सफल नहीं रहे।

16.7 शब्दावली

पूँजी-प्रधान उद्योग : वे उद्योग जिनमें श्रम की प्रति इकाई पर अधिक पूँजी लगती है।

आर्थिक आधारिक संरचना : से अभिप्राय उन प्रायोजनाओं से होता है जिनमें विद्युत शक्ति, सिंचाई, परिवहन और संचार के उत्पादन पर बल दिया जाता है।

भारी उद्योग : के अंतर्गत लोहा और इस्पात, भारी मशीनरी, इंजीनियरी उद्योग, बिजली, कोयला और भारी रसायन आते हैं, जिनका संबंध पूँजीगत पदार्थ क्षेत्रक से होता है।

औद्योगिक रुग्णता : तब मानी जाती है जब किसी औद्योगिक इकाई में एक के बाद दूसरे वर्ष में हानि होती रहती है और इस प्रक्रिया में उसकी निवल संपत्ति में कमी होती है।

उद्योगीकरण : आर्थिक विकास की एक प्रणाली जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के मुख्य भाग का उपयोग तकनीकी रूप से अद्यतन और बहुशाखी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए किया जाता है, जो समस्त अर्थव्यवस्था में तेजी से संवृद्धि ला सके और आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर कर सके।

निवल संपत्ति : इससे अभिप्राय होता है प्रदत्त पूँजी और मुक्त रिजर्व का योग। मुक्त रिजर्व का अर्थ होता है लाभों और शेयर प्रीमियम खाते से क्रेडिट किए गए सभी रिजर्व।

16.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Ruddar Datt and KPM Sundaram (1999), *Indian Economy*, 38th Ed. S.Chand & Co., New Delhi.

Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, (1994-95).

Government of India (1961), Problems in Third Plan- A Critical Miscellany.

Planning Commission (1961), Second Five Year Plan - The Framework.

Shirokov, G.K. (1973), *Industrialisation of India*, Peoples' Publishing House, New Delhi.

16.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा-संकेत

बोध प्रश्न 1

1) उत्तर के लिए भाग 16.2 में पढ़े।

बोध प्रश्न 2

क) औद्योगिक क्षेत्रक माध्यमिक क्षेत्रक का ही एक अंग है। माध्यमिक क्षेत्रक में उद्योगों के साथ-साथ विनिर्माण गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं।

ख) औद्योगिक क्षेत्रक में उत्पादन के अतिरिक्त विद्युत और खनन भी शामिल है।

ग) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं ज्यादा लम्बे समय तक प्रयोग में आती है। जबकि अल्पकालिक उपभोक्ता वस्तु केवल एक बार प्रयोग में आती है।

बोध प्रश्न 3

क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी एक्ट 1985 के अनुसार रुग्ण इकाई वह है जिसका संचित हानि उसके कुल मूल्य से अधिक या उसके बराबर है। इसके अतिरिक्त इस कम्पनी ने वर्तमान वित्त वर्ष और उससे पहले वित्त वर्ष में भी घाटा भुगता हो।

ख) बड़े और मध्यम उद्योगों में औद्योगिक रुग्णता के मुख्य कारण है:

1) सरकारी नीतियाँ
2) सरकार की प्राथमिकताओं में परिवर्तन
3) विद्युत और कच्चे माल की कमी
4) बिगड़ते औद्योगिक संबंध
5) कु-प्रबंधन

ग) लघु उद्योगों में औद्योगिक रुग्णता के मुख्य कारण हैं:

1) व्यापार प्रबंधन के आधारभूत मूल्यों का पालन न होना
2) क्षमता का कम उपयोग
3) मूल्यों द्वारा भुगतान न करना ।